भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1542
सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

आईटीआई का उन्नयन

1542. **श्री इटेला राजेंदर:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन की योजना हमारे भावी कार्यबल के कौशल को बढ़ाने और अगले पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास में सहयोग देने के लिए एक नई योजना लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि युवा आबादी भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में आज की तिथि तक स्वीकृत और उपयोग की गई धनराशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र वार विशेषकर तेलंगाना के लिए ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ख): मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास और उन्नत आईटीआई के माध्यम से रोजगार क्षमता में परिवर्तन (पीएमसेतु) योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. आईटीआई और एनएसटीआई में प्रशिक्षण वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में उद्योग-अनुकूल दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. मांग-संचालित कौशल और बेहतर रोजगार परिणामों के लिए उद्योग संबंध को मजबूत करना; और
v. शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता बढ़ाना।

इस योजना में दो घटक शामिल हैं:

घटक I - हब और स्पोक मॉडल में 1,000 सरकारी आईटीआई (200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई) का उन्नयन। इन आईटीआई को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब, डिजिटल कंटेंट और उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप नए पाठ्यक्रमों के साथ अपग्रेड किया जाएगा।

घटक II - भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और लुधियाना में स्थित पांच एनएसटीआई की क्षमता वृद्धि, जिसमें वैश्विक भागीदारी के साथ प्रशिक्षकों के उन्नत प्रशिक्षण पर ध्यान देने के साथ-साथ कौशल के लिए क्षेत्र-विशिष्ट राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करना शामिल है।

मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को नए मांग-संचालित पाठ्यक्रमों, मौजूदा ट्रेडों में सुधार, उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है, जिससे युवाओं को कल के उद्योग जगत और रोजगार बाजार की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके।

इस योजना का कुल अनुमानित परिव्यय ₹60,000 करोड़ है, जिसमें पांच साल की अवधि में केंद्र सरकार (₹30,000 करोड़), राज्य सरकारों (₹20,000 करोड़), और उद्योग भागीदारों (₹10,000 करोड़) का योगदान है।

पीएम-सेतु योजना के तहत आईटीआई का चयन संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा उद्योग जगत के परामर्श से किया जाता है, जो उभरती कौशल आवश्यकताओं और स्थानीय औद्योगिक क्षमता के अनुरूप सुनिश्चित किया जाता है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उद्योग जगत भागीदारों के सहयोग से चिन्हित आईटीआई क्लस्टर के उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है।

वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तेलंगाना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ही योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए निधियां संवितरित की जाएंगी।

*****